

# वेस्टर्न डीएफसी पर निर्माण कार्यों में आएगी संपत्ताएं

10 दिसंबर 2015 को डीएफसीआईएल ने 2390 करोड़ रुपये के सिग्नलिंग और टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। सिग्नलिंग और टेलीकॉम के क्षेत्र में यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट 1780 करोड़ रुपये का है। जिसके अंतर्गत 915 किमी की रेवारी से वडोदरा के बीच डबल लाइन में सिग्नलिंग का कार्य होगा। इस प्रोजेक्ट में लेड पार्टनर के रूप में हितैची लिमिटेड एवं मितिसुई टेक्समैको, हितैची इंडिया लिमिटेड भी सहयोगी कंपनियों के रूप में शामिल रहेंगी। 610 करोड़ रुपये के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में रेवारी और जेएनपीटी के बीच 1370 किमी लंबे रूट पर ट्रेन प्रॉटेक्शन एंड वॉर्निंग सिस्टम (टीपीडब्ल्यूएस) लगाया जाएगा। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े सम्बूद्धों पर डीएस राना डायरेक्टर इंफ्रा, डीएफसीसीआईएल और मिनो, डिप्टी जनरल मैनेजर हितैची लि. जापान ने डीएफसीसीआईएल के मैनेजिंग डायरेक्टर आदेश शर्मा की मौजूदगी में हस्ताक्षर

किए। इस पूरे प्रोजेक्ट को जेआईसीए द्वारा फंडिंग की जाएगी।

## लगतारा बढ़ते कंदम

डीएफसीसीआईएल देश में फ्रेट कॉरिडोरों के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मैटेनेंस के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वर्तमान में कंपनी दो फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर रही है। पहले चरण में ईस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना से दानकुनी (1840 किमी) और वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से जेएनपीटी (1520 किमी) का निर्माण हो रहा है। पूरे वेस्टर्न कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कॉओपरेशन एंजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। जबकि वेस्टर्न कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय मदद की है।

## सीएसआर से स्कील डेवलपमेंट

डीएफसीसीआईएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत ग्रामीणों को सरकारी आईटीआई केंद्रों में विशेष

## इन एडवांस तकनीकों का होगा प्रयोग

- इलेक्ट्रॉनिक इनटरलॉकिंग
- मल्टी सेवान डिजीटल एक्स्प्रेस काउटर्स
- ट्रेन मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम
- ओएफसी पर आधारित कम्यूनिकेशन
- जीएसएम-आर

प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में पूर्वी डीएफसीसीआईएल के यमुनानगर अंबाला और सहारनपुर ज़िलों के लगभग 75 गांवों के 150 लोगों को चयनित किया गया है। इन लोगों को तीन महीने का स्किल डिवेलपमेंट कोर्स कराया जाएगा जो रेफिंजरेशन ऐंड एयर कंडीशनर, बेसिक इलेक्ट्रिक ऐंड हाइड्रस वायरिंग और टू ऐंड फोर व्हीलर ऑटो सर्विसिंग जैसे विषयों से संबंधित होंगे। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन रोज़गार परक प्रशिक्षण कोसों से नौकरी एवं स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। प्रशिक्षण का सारा खर्च डीएफसीसीआईएल वहन करेगी।

